



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052020-219317
CG-DL-E-09052020-219317

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1285]
No. 1285]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 9, 2020/वैशाख 19, 1942
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 9, 2020/VAISAKHA 19, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2020

का.आ.1435(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम 2010, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम 2011, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) द्वितीय संशोधन नियम 2011, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम 2013, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम 2014 और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम 2015 और बोली की नियत तारीख तक के संशोधन और अधिसूचना संख्या का.आ. 2049 (अ), तारीख 23 अगस्त 2012, का.आ. 1783(अ), तारीख 09 अगस्त, 2012 और का.आ. 505 (अ), तारीख 04 मार्च, 2013 के अधिक्रमण में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या का.आ. 2162 (अ), तारीख 07 जुलाई 2017 द्वारा राजस्थान राज्य में, राष्ट्रीय राजमार्ग- 79 के किशनगढ़-उदयपुर-अहमदाबाद सेक्शन के 90.000 कि.मी. (डिज़ाइन चेनेज) से 214.870 कि.मी. (डिज़ाइन चेनेज) (विद्यमान चेनेज 69.730 कि.मी. से 163.950 कि.मी. और 0.000 कि.मी. से 29.600 कि.मी.) (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त सेक्शन" कहा गया है) तक के छह लेन में रासविप चरण-V के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण(डीबीएफओटी) आधार पर विकास करने हेतु मेसर्स सी जी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड को शुल्क संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत किया था;

अब, , केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए का. आ. 2162 (अ), तारीख 07 जुलाई 2017 के द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है-

अधिसूचना के पैरा 3 को निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा:-

“3. करार के अनुसार परियोजना समापन की तारीख और वास्तविक रूप में परियोजना को समापन करने की तारीख तक हुए विलंब के लिए किसी प्रकार का प्रयोक्ता शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इस नियम के प्रयोजन हेतु परियोजना के किसी अनंतिम समापन को परियोजना का समापन नहीं माना जाएगा।”

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/600/सीओ/16-17/जीसी केयूए (90.000 कि.मी. से 214.870 कि.मी.) सेक्शन बीओटी]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2020

S.O. 1435 (E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 read along with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2010, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2011, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment Rules, 2011, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2013, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 and National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2015 and its subsequent amendments up to bid due date and in supersession of the Notification No. S.O. 2049(E) dated 23rd August, 2012, S.O. No. 1783(E) dated 09th August, 2012 and S.O. No. 505(E) dated 04th March, 2013, the Central Government, vide notification S.O. 2162(E) dated 07th July, 2017, authorized M/s. CG Tollway Private Limited to collect and retain the fee for the development of Kishangarh - Udaipur- Ahmedabad Section from km. 90.000 (design chainage) to km. 214.870 (design chainage) (existing chainage from km. 69.730 to km. 163.950 and from km. 0.000 to km. 29.600) (hereinafter referred to as the “said section”) of the NH-79 in the state of Rajasthan to Six lane through Public Private Partnership under NHDP Phase-V on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification published vide S.O. 2162(E) dated 07th July, 2017:-

Para 3 of the notification shall be read as follows:-

“3. No user fee shall be levied for the delayed period between the date of completion as per agreement and the date of actual completion of the project, if it is delayed. For the purposes of this rule, any provisional completion of the project shall not be treated as completion of the project.”

[F. No. NHAI/13013/600/CO/16-17/GC KUA (km. 90.000 to km. 214.870) Section BOT]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.